मंजूर की गयी सहायता की सूचना क्रमशः अनुबंध 1 और 2 में दी गयी है। (देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र संख्या 27 और 28)

केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और उस पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर अनुबंध 1 और 2 में दर्शायी गयी व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गयी है।

(ग) चूंकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गयी है, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

सूखा और बाढ़ से प्रभावित जिले

758. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कौन-कौन से जिले सूखाग्रस्त तथा बाढ़ग्रस्त हुए हैं;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति व मवेशी प्रभावित हुए हैं;

(ग) इससे कितना वित्तीय नुक्सान होने की संभावना है; और

(घ) ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने और ऐसी आपदाओं के दूरगामी तथा अन्य प्रभावों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) (क) 1987-88 में सूखे तथा बाढ़ से प्रभावित हुए जिलों से संबंधित सूचना क्रमशः अनुबंध 1 और 2 में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र संख्या 29 और 30]

(ख) सूखे और बाढ़ की चपेट में आये व्यक्तियों तथा पशुओं की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) बाढ़ के कारण हुई वित्तीय हानि, अनुमानित और प्रभावित राज्यों द्वारा सूचित, कुल 1312.08 करोड़ रुपये बनती है। सूखे के कारण हुई वित्तीय हानि संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हुई स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये विभिन्न विशेष कदम उठाये हैं। इनमें से कुछेक उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) सूखे से प्रभावित ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई में वृद्धि करना।

(2) जहां पर चारे की कमी महसूस की गई हो वहां पर चारे तथा चारे की ढुलाई की व्यवस्था करना।

(3) छोटे और सीमांत किसानों को बीजों की सप्लाई और कृषि आदानों के लिये राज सहायता की व्यवस्था करना।

(4) सब्जियों की सप्लाई और चारे की खेती में वृद्धि के लिये विशेष योजनाएं।

(5) कृषि क्षेत्र को बिजली की सप्लाई में प्राथमिकता।

(6) पीने तथा सिंचाई के प्रयोजन के लिये जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।

(7) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिये पूरक पोषण की व्यवस्था करना।

(8) सूखा से बचाव प्रदान करने के लिये चुनिन्दा सिंचाई परियोजनाओं को तेज करना।

(9) राहत कार्यों के लिये नियुक्त किए गए व्यक्तियों में वितरण के लिये राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन।

विवरण

1987 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनसंख्या तथा पंडित पशुओं की संख्या संबंधी ब्यौरे :

I. सूखा :

1. प्रभावित जनसंख्या : 2854.45 लाख

2 प्रभावित पशुओं की संख्या . . . 1636.84 लाख

II. **बाढ़ / ओला / भारी वर्षा :**

1. प्रभावित जनसंख्या... 515.92 लाख
2. मरे व्यक्तियों की संख्या . . . 1565
3. मरे पशुओं की संख्या . . . 76920

राज्यों को खाद्य तेल का आवंटन

759. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को खाद्य तेल की मासिक आवश्यकता क्या है उनके द्वारा कितने खाद्य तेल की मांग की गई है और पिछले तीन वर्षों में केन्द्र द्वारा उन राज्यों को कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई; खाद्य तेलों के उत्पादन में उसके उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कितनी कमी रही;

(ख) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, खाद्य तेल की कितनी अतिरिक्त मात्रा का आयात किया गया है या किए जाने की संभावना है; इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) खाद्य तेलों के मूल्यों में किस सीमा तक तेजी व मंदी रही है और किस अवधि के दौरान वे बढ़े या घटे हैं, कीमतों को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयातित तेल के लिए अपनी मांग समूचे तेल वर्ष के लिए देते हैं। पिछले तीन तेल वर्षों में आयातित खाद्य तेल की मांग, आवंटन तथा उनकी उठाई गई मात्रा निम्नवत हैं :—

(मात्रा मीटरी टनों में)

तेल वर्ष	मांग	आवंटन	उठाई गई मात्रा
1984–85	1440310	727120	660489
1985–86	1439160	702930	597144
1986–87	1390186	834080	740239

कृषि मंत्रालय ने 1986–87 के दौरान तिलहनों के उत्पादन के लिए 148 लाख मीटरी टन का लक्ष्य रखा था, जिसकी तुलना में उत्पादन 115–120 लाख मीटरी टन के आसपास होने की आशा है। इस प्रकार, तेल वर्ष 1986–87 में खाद्य तेलों की उपलब्धता में लगभग 8.4 से 9.9 लाख मीटरी टन की कमी होने का अनुमान है।

(ख) आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति देशीय खाद्य तेलों की सप्लाई के अ पूरक के रूप में होती है। तथापि, अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि की गई है। तेल वर्ष 1985–86 के मुकाबले तेल वर्ष 1986–87 के दौरान 30–9–87 तक आयात किए गए खाद्य तेलों की कुल मात्रा निम्नवत है :—

	तेल वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर)	
	1985–86	1986–87 (30–9–87 तक)
मात्रा लाख मीटरी टनों में	11.79	12.01
मूल्य (करोड़ रुपयों में)	667.67	538.49

(ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में कुछ प्रधान खाद्य तेलों के बाजार मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (**नीचे** देखिए) मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नवत हैं :